Rajasthan Receives ₹537.70 Crore Under Jal Jeevan Mission 2.0

The Government of India has approved ₹537.70 crore as central assistance for Rajasthan under Jal Jeevan Mission (JJM) 2.0 for the financial year 2026–27. The Rajasthan government had to push for the approval from the Ministry of Jal Shakti which was given after efforts to improve the infrastructure of rural drinking water supply in the state.

Key Highlights

- Under the Jal Jeevan Mission 2.0, the Central Government sanctioned ₹537.70 crore for Rajasthan.
- The funding is for support of rural drinking water supply projects throughout the state.
- The reimbursement covers costs of the transition between JJM Phase 1 and Phase 2.
- The mission is to offer secure and suitable drinking water to each household in the rural areas that are covered under the "Har Ghar Jal" project.
- The Jal Jeevan Mission-2.0 has been extended till December 2028.

Category-wise Fund Allocation

Category	Allocation
General Areas	₹307.45 crore

Scheduled Caste (SC) Areas	₹177.73 crore
Scheduled Tribe (ST) Areas	₹52.52 crore
Total	**₹537.70 crore**

Importance

The approved funds will be used to expedite rural water pipelines, upgrade water purification facilities, and provide potable water to remote villages and tribal areas. The project also contributes towards government's goal of equitable distribution of water to the people of all walks of life.

Conclusion

The approval of ₹537.70 crore under Jal Jeevan Mission 2.0 is a major contribution to the enhancement of the Rural Water Infrastructure in the state of Rajasthan. The funding will go toward providing more piped drinking water, enhancing water quality and creating equitable access to safe drinking water in General, SC, and ST areas. The programme aligns with the Government of India's vision "Har Ghar Jal" and helps in the sustainable development of the rural population by improving public health and quality of life in the state.

MCQs

Q1. Which ministry approved ₹537.70 crore for Rajasthan under Jal Jeevan Mission 2.0?
A. Ministry of Rural Development
B. Ministry of Housing and Urban Affairs
C. **Ministry of Jal Shakti**
D. Ministry of Environment

Answer: C

Q2. The approved assistance is meant for which state?
A. Gujarat
B. Madhya Pradesh
C. Haryana
D. **Rajasthan**

Answer: D

RASonly

Q3. Jal Jeevan Mission primarily aims to provide:
A. Free electricity to villages
B. Rural internet connectivity
C. **Safe tap water to every rural household**
D. Housing for all

Answer: C

Q4. Till when has the implementation period of Jal Jeevan Mission 2.0 been extended?
A. December 2026
B. March 2027
C. December 2027
D. **December 2028**

Answer: D

राजस्थान को जल जीवन मिशन 2.0 के तहत ₹537.70 करोड़ की केंद्रीय सहायता

भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष **2026–27** के लिए जल जीवन मिशन **(JJM) 2.0** के तहत राजस्थान को **₹537.70** करोड़ की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की है। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति अवसंरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार के प्रयासों के बाद जल शक्ति मंत्रालय ने इस सहायता को मंजूरी दी।

मुख्य बिंदु

- जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए **₹537.70** करोड़ की स्वीकृति प्रदान की।
- यह राशि राज्यभर में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए दी गई है।
- यह सहायता **JJM Phase 1** और **Phase 2** के बीच संक्रमण अवधि में किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में दी जा रही है।
- इस मिशन का उद्देश्य "हर घर जल" अभियान के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है।
- जल जीवन मिशन **2.0** की अवधि को दिसंबर **2028** तक बढ़ा दिया गया है।

श्रेणीवार निधि आवंटन

RASonly

श्रेणी	आवंटन
सामान्य क्षेत्र	₹307.45 करोड़
अनुसूचित जाति (SC) क्षेत्र	₹177.73 करोड़
अनुसूचित जनजाति (ST) क्षेत्र	₹52.52 करोड़
कुल	**₹537.70** करोड़

महत्व

स्वीकृत राशि का उपयोग ग्रामीण जल पाइपलाइन परियोजनाओं में तेजी लाने, जल शुद्धिकरण सुविधाओं को उन्नत करने तथा दूरस्थ गांवों और जनजातीय क्षेत्रों तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के लिए किया जाएगा। यह पहल समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से जल उपलब्ध कराने के सरकार के उद्देश्य को भी मजबूत करती है।

निष्कर्ष

जल जीवन मिशन 2.0 के तहत **₹537.70** करोड़ की स्वीकृति राजस्थान के ग्रामीण जल अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सहायता अधिक घरों तक पाइपलाइन से पेयजल पहुंचाने, जल गुणवत्ता में सुधार करने तथा सामान्य, SC और ST क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की समान उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगी। यह कार्यक्रम भारत सरकार के "हर घर जल" विजन के अनुरूप है और ग्रामीण क्षेत्रों में जनस्वास्थ्य तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देता है।

MCQs

Q1. जल जीवन मिशन **2.0** के तहत राजस्थान के लिए **₹537.70** करोड़ की स्वीकृति किस मंत्रालय ने दी?

A. ग्रामीण विकास मंत्रालय
B. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
C. जल शक्ति मंत्रालय
D. पर्यावरण मंत्रालय

उत्तर: C

RASonly

Q2. स्वीकृत केंद्रीय सहायता किस राज्य के लिए है?
A. गुजरात
B. मध्य प्रदेश
C. हरियाणा
D. राजस्थान

उत्तर: D

Q3. जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
A. गांवों में मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना
B. ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना
C. प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित नल जल उपलब्ध कराना
D. सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना

उत्तर: C

Q4. जल जीवन मिशन **2.0** की अवधि कब तक बढ़ाई गई है?
A. दिसंबर 2026
B. मार्च 2027
C. दिसंबर 2027
D. दिसंबर 2028

उत्तर: D

RASonly